



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2010/चैत्र 26, 1932

No. 104]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2010/CHAITRA 26, 1932

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 13 अप्रैल, 2010

सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यू एस.—पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुपालन में और 'महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' के खंड 1.2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, 31 मार्च, 2005 को आदेश सं. टीएएमपी/23/2003-डब्ल्यूएस द्वारा अधिसूचित 'महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस

आदेश

(अप्रैल, 2010 के 7वें दिन पारित)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निर्देशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च, 2005 को राजपत्र सं. 39 द्वारा भारत के राजपत्र में 'महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' अधिसूचित किए गए थे। ये दिशानिर्देश 31 मार्च, 2005 से प्रभावी हुए थे और दिशानिर्देशों के खंड 1.2 में यथा विनिर्दिष्ट, 5 वर्षों की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2010 तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा पहले समीक्षित अथवा विस्तारित नहीं किया जाता है।

2. पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार ने अपने पत्र सं. पीआर-14019/20/2009-पीजी दिनांक 1 अप्रैल, 2010 द्वारा इस प्राधिकरण को सलाह दी है कि 'महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' की वैधता को एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया जाए।

3. तदनुसार, 'महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2004' की वैधता 31 मार्च, 2010 से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित की गई है।

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/143/09/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th April, 2010

No. TAMP/21/2009-WS.—In compliance of the direction issued by the Government of India in Ministry of Shipping (MOS) and in exercise of the powers conferred under clause 1.2 of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004', the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' notified *vide* Order No. TAMP/23/2003-WS on 31st March, 2005, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/21/2009-WS

ORDER

(Passed on this 7th day of April, 2010)

The 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' were notified in the Gazette of India on 31st March, 2005 *vide* Gazette No. 39 by this Authority in compliance of policy directions issued by the Government of India under section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963. These guidelines came into effect from 31st March, 2005 and as stipulated in clause 1.2 of the guidelines, will remain in force for a period of 5 years, i.e. up to 31st March, 2010, unless reviewed earlier or extended by this Authority.

2. The Government of India in Ministry of Shipping *vide* its letter No. PR-14019/20/2009-PG, dated 1st April, 2010 has advised this Authority to extend the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

3. Accordingly, the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' is extended for a period of one year from 31st March, 2010 or until further orders whichever is earlier.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT-III/4/143/09/Exty.]